(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम क्या-क्या हैं तथा महिलाओं के प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

Joint venture with Hongkong based Consolidated Electric Power Asia Limited

1742. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have asked Hongkong based Consolidated Electric Power Asia Limited (CEPA) to float a separate joint venture to develop the captive coal mine and put up a washery at the pit head in Orissa, as reported in the Hindustan Times dated 21st November, 1996;

(b) if so, the details thereof, indicating the proposed total installed capacity of the project and CEPA's minimum controlling stake; and

(c) whether CEPA has finalised details for fuel linkage in consultation with CIL indicating quantity of coal likely to be supplied for the Hirma plant in addition to the million tonnes being supplied by CIL to plant?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (c) M/s. Consolidated Electric Power Asia Ltd. (CEPA) are proposing to set up a 6×660 MW power station at Hirma in Orissa. Their requirement of coal is 18 mtpa. Coal India has agreed to a long term coal linkage of 12 mtpa for the above power station. Discussion on Fuel Supply Agreement (FSA) have started between CIL and power company., For the balance 6 mtpa of coal requirement the power Company nas requested for identification of a captive mining block. The proposal is under consideration of the Screening Committee of Ministry of Coal in consultation with CIL. Operation of the captive mining block by a joint venture company is an option available to the promoters.

खुली और लेवी चीनी के अनुपात में परिवर्तन

1743. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुली और लेवी चीनी के अनुपात में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) चीनी का क्या सीजन प्रारंभ होने के पहले पिछले तीन वर्षों में चीनी का भंडार कितना रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के संबंध में मिलों पर बकाया राशि कितनी है; और

(घ) चीनी का बफर स्टाक बढ़ाने के लिए क्या नीति बनाई जा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) फिलहाल, आंशिक नियंत्रण की चीनी नीति में दिए गए मुक्त बिक्री और लेवी चीनी के वर्तमान 60:40 के अनुपात में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अगला चीनी मौसम शुरू होने से पहले चीनी का स्टाक निम्नानुसार था:—

चीनी मौसम	निम्न तारीख को	स्टाक लाख टन में
1993-94	30.9.1994	21.93
1994-95	30.9.1995	54.95
1995-96	30.9.1996	लगभग 81.00

(ग) 30 सितम्बर को स्थिति के अनुसार पिछले तीन चीनी मौसमों के लिए गन्ने के कुल देय

मूल्य के संबंध में बकाया राशि की प्रतिशतता निम्नानुसार थी:—

चीनी मौसम	निम्न तारीख को	प्रतिशतता
1993-94	30.9.1994	1.12
1994-95	30.9.1995	2.16
1995-96	30.9.1996	6.97

(घ) सरकार ने पहले से ही सृजित 5 लाख टन चीनी के बफर स्टाक को एक वर्ष तक और बनाए रखने तथा एक वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टाक सृजित करने का निर्णय लिया है।

Demand for Secret Ballot for Recognition of Trade Unions

1744. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a demand for introducing secret ballot for recognition of trade unions; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Cretain Central Trade Union Organisations submitted a memorandum to the Prime Minister urging the Government to frame suitable legislation for recognition of trade unions by Secret Ballot. The issue of determination of the representative character of Trade Unions by Secret Ballot has been referred to the Bipartite Committee constituted by the Ministry of Labour and consisting of representatives of employers and workers. Further course of action will depend on the recommendation of the committee.

खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के उपाय

1745. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिजों के निर्यात में समिति वृद्धि के लिये कौन-कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात हेतु खनिजों के खनन कार्य में निवेश करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु कोई समयबद्ध कदम उठाए है अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) खनिज निर्यात संबंधी राशि में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में इसमें 11% की बढ़ोत्तरी हुई। खनिज क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1993 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में भी संशोधन किया गया इससे अनेक क्षेत्रों में निवेश करने में सुविधा होगी जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन करने जिससे खनिज क्षेत्र का विकास होगा और निर्यात-अर्जन में वृद्धि होगी।

Waivers of Anti-Dumping Duties

1746. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the All India Flat Tape Manufactures and All India Plastic Woven Sacks Manufacturers have given some representations for redressal of their grievances on walver of anti-dumping duty by the European Union;

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have taken any action the matter;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons thereof?